लोगों को रोजगार देकर स्वावलंबी बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता : योगी

मुख्यमंत्री ने 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपये के ऋण ऑनलाइन वितरित किए

ओडीओपी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 13 सीएफसी का शिलान्यास और 6 का लोकार्पण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रयासरत है। लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नई एमएसएमई इकाइयों के लिए आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपये के ऋण ऑनलाइन वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग की ओर से संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए प्रशिक्षण योजना और ओडीओपी-विपणन प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान के उद्देश्य से एमएसएमई विभाग और एकेटीयू के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ई-बे के साथ भी एमओयू दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि विवि से संबद्ध 756 कॉलेजों के विद्यार्थी ओडीओपी से जुड़ेंगे।

अब तक 2.71 लाख नई इकाइयों को 8,949 करोड़ के ऋण वितरित

गत 14 मई को आयोजित ऑनलाइन लोन मेला में लगभग 57 हजार नई इकाइयों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का ऋण ऑनलाइन वितरित किया गया था। 26 जून को प्रधानमंत्री ने 1 लाख 35 हजार नई इकाइयों को लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत और वितरित किए। इस तरह प्रदेश में अब तक 2 लाख 71 हजार 743 नई इकाइयों को लगभग 8,949 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

साथ ही इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्वरोजगार को गति देने का काम भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना के तहत 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास और प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 6 सीएफसी का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, 'ओडीओपी', मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग-अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एमएसएमई विभाग ने

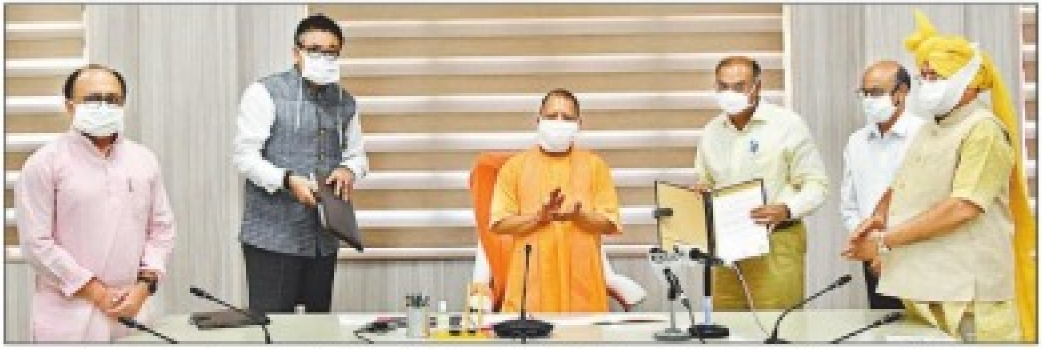

एमएसएमई इकाइयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ई-बे के साथ एमओयू किया गया।

आर्थिक पैकेज का बेहतर उपयोग किया है।

मुख्यमंत्री ने इन सामान्य सुविधा केंद्रों से संबंधित प्रवर्तक और सुविधा केंद्रों का संचालन करने वाली संस्थाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यूपी संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रदेश के नौजवानों को स्वावलंबी बनाकर उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रदेश का नवनिर्माण होगा।

एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार कोविड-19 में भी संभावनाओं को तलाश रही है। इसके लिहाज से एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को ऋण वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर एमएसएमई राज्यमंत्री उदयभान सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल, एकेटीयू के वीसी प्रो. विनय कुमार पाठक तथा विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सुचारु नहीं मिला तो जिलाधिकारी की जवाबदेही

सीएम ने मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबंध करने के दिए निर्देश

कहा-सरकारी, निजी अस्पतालों में आग से बचाव की प्रभावी व्यवस्था की जाए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में राज्य मुख्यालय तथा जिलों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सुचारु रूप से कार्य नहीं करेगा तो संबंधित जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले में की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन सुबह-शाम नियमित तौर पर समीक्षा करें। उन्होंने डीजी फायर सर्विस को आग से बचाव के संबंध में सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो